

विधि और न्याय मंत्रालय
सं 66 (विनियोग)
भारत का उच्चतम न्यायालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	258.53	...	258.53	269.46	...	269.46	296.55	...	296.55	308.61	...	308.61
<i>वसूलियां</i>
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	258.53	...	258.53	269.46	...	269.46	296.55	...	296.55	308.61	...	308.61
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. भारतीय उच्चतम न्यायालय	258.53	...	258.53	269.46	...	269.46	296.55	...	296.55	308.61	...	308.61
कुल जोड़	258.53	...	258.53	269.46	...	269.46	296.55	...	296.55	308.61	...	308.61
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. न्याय प्रशासन	258.53	...	258.53	269.46	...	269.46	296.55	...	296.55	308.61	...	308.61
जोड़-सामान्य सेवाएं	258.53	...	258.53	269.46	...	269.46	296.55	...	296.55	308.61	...	308.61
कुल जोड़	258.53	...	258.53	269.46	...	269.46	296.55	...	296.55	308.61	...	308.61

1. **भारतीय उच्चतम न्यायालय:** यह विनियोग भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक और अन्य व्यय का प्रावधान करता है। इसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों, विभागीय कैंटीन सहित रजिस्ट्री के स्टाफ एवं अधिकारियों के वेतन और यात्रा व्यय, स्टेशनरी, कार्यालय उपकरणों, सुरक्षा उपकरणों, सीसीटीवी के रख-रखाव और उच्चतम न्यायालय की वार्षिक रिपोर्ट का मुद्रण सहित सुरक्षा के लिए तैनात कर्मियों के लिए व्यावसायिक सेवा प्रभार और स्थापना संबंधी जरूरतों पर व्यय का प्रावधान शामिल है।